प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

विषय:—हैल्पेज इण्डिया सी० 14 कुतुब इन्स्टीट्यूट एरिया, नई दिल्ली को ग्राम गिवांला प०क्षे० गणेशनगर, तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग में आयी भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं (आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल) की स्थापना हेतु 0.314 है० भूमि क्रय की अनुमित प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या—4783/सात—2(2013—14) दिनांक 18.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, हैल्पेज इण्डिया सी0 14 कुतुब इन्स्टीट्यूट एरिया, नई दिल्ली को ग्राम गिवांला प0क्षे0 गणेशनगर, तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग में आयी भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं (आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल) की स्थापना हेतु 0.314 है0 भूमि क्रय की अनुगति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(1) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

- 1— केता धारा 129 ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमित से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल) के लिये करेगा, जिसके लिये

11— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभाग (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से विधिक व अन्य अनापितत / स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

12— भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13— उपरोक्त प्रतिबन्धों / शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

> भवदीय, (भास्करानन्द) सचिव।

पृ०प०सं०— २६५० / समदिनांकित / 2014 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- प्रमुख सविव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— डॉ० आपगा सिंह राज्य प्रभारी कार्यालय, हैल्पेज इण्डिया, 180 इन्द्रानगर, बसन्त बिहार, देहरादून।
- 5 निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी) उप सचिव।